RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 319
दि. 23.03.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सतर्क: पीएम मोदी की मैराथन बैठक में ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस, हर हाल में आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश

जीएनएस)। New Delhi। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्क और सक्रिय रणनीति अपनाई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने रविवार शाम अपने आवास पर करीब साढ़े तीन घंटे तक चली एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देश में पेट्रोल, गैस, बिजली और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति पर मंथन किया गया।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा दिया है। खासतौर पर Strait of Hormuz में उत्पन्न गतिरोध ने तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है।

प्रधानमंत्री की इस अहम बैठक में Amit Shah, Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman, S. Jaishankar, J. P. Nadda और Hardeep Singh Puri सहित कई वरिष्ठ मंत्री और उच्चाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, भंडारण क्षमता और वितरण तंत्र जैसे अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि देश के किसी भी हिस्से में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस या बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मंत्रालयों से कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए हर स्तर पर तैयारियां मजबूत रखी जाएं और किसी भी संभावित संकट की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन

नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईंधन की समय पर डिलीवरी और उद्योगों को निर्बाध सप्लाई बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर पड़ता है।

बैठक में यह भी सामने आया कि भारत सरकार पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कूटनीतिक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि भारत ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, फ्रांस, मलेशिया, इजरायल और ईरान जैसे देशों के नेताओं से बातचीत कर स्थिति का आकलन किया है और आपूर्ति बनाए रखने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर भी काम किया जा रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक मंत्रालयों ने अपनी-अपनी तैयारियों का विवरण प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि देश में फिलहाल ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई चेन को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से स्टॉक मैनेजमेंट और आपूर्ति की निगरानी पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं और उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाए। साथ ही यह भी तय किया गया कि यदि हालात बिगड़ते हैं, तो रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि देश में किसी प्रकार की कमी न हो।

बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की स्थिति में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करना जरूरी है, ताकि पूरे देश में एक समान रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि ऐसे समय में धैर्य, सतर्कता और रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी संभावित जोखिम का समय रहते समाधान निकाला जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी प्रकार का व्यवधान वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में भारत की यह सक्रिय तैयारी और कूटनीतिक पहल भविष्य में संभावित संकट से निपटने में अहम भूमिका निभा सकती है।

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह हाई-लेवल बैठक भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि वैश्विक संकट चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, देश में पेट्रोल, गैस और बिजली की आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे।

पंजाब में OTS स्कीम का असर: 111 करोड़ की वसूली डेडलाइन के बाद 8 हजार संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई तय

जीएनएस)। Chandigarh। पंजाब सरकार की वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। राज्य के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने जानकारी दी कि अब तक इस स्कीम के तहत 298.39 करोड़ रुपये के बकाये से जुड़े 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 111.16 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। सरकार इसे राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ पुराने कर विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

वित्त मंत्री ने बताया कि यह स्कीम उन व्यापारियों के लिए विशेष राहत लेकर आई है, जो वर्षों से लंबित वैट बकाये के बोझ तले दबे हुए थे। इस योजना के तहत उन्हें ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे वे कम राशि में अपने पुराने मामलों का निपटान कर सकते हैं। इससे न केवल व्यापारियों को राहत मिल रही है, बल्कि सरकार को भी राजस्व संग्रह में तेजी देखने को मिल रही है। सरकार के अनुसार, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख शहरों और डिवीजनों से इस स्कीम को जबरदस्त समर्थन मिला है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने आगे आकर अपने बकाये का निपटान करने में रुचि दिखाई है। अधिकारियों का मानना है कि यह रुझान दर्शाता है कि सरकार की नीतियों के प्रति व्यापारिक समुदाय में विश्वास बढ़ रहा है और वे विवादों को समाप्त कर नियमित कर व्यवस्था में लौटना चाहते हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह स्कीम केवल सीमित अवधि के लिए लागू है और 31 मार्च 2026 इसकी अंतिम तिथि है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने सभी लंबित वैट बकाये का निपटान समय रहते कर लें, क्योंकि इसके बाद सरकार का रुख पूरी तरह सख्त हो जाएगा।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समय सीमा समाप्त होते ही किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और बकाया वसूली के लिए कठोर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकार ने पहले ही लगभग 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली है, जिन पर वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें संपत्तियों की कुर्की, बैंक खातों को फ्रीज करना और अन्य कानूनी उपाय शामिल हो सकते हैं।

सरकार का मानना है कि इस तरह की सख्ती उन व्यापारियों के लिए जरूरी है, जो जानबूझकर कर भुगतान से बचते रहे हैं। वहीं, जो व्यापारी स्वेच्छा से स्कीम का लाभ उठाकर अपने बकाये का निपटान कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन और राहत दी जा रही है। इस संतुलित दृष्टिकोण से सरकार एक ओर राजस्व बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी ओर व्यापारिक माहौल को भी सकारात्मक बनाए रखना चाहती है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी और व्यापार-हितैषी नीतियों पर काम कर रही है। OTS स्कीम इसी सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पुरानी कर देनदारियों को समाप्त कर नई शुरुआत का अवसर देना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएं सरकार और व्यापारियों के बीच विश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इससे एक ओर जहां सरकार को लंबित राजस्व प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को भी कानूनी झंझटों और अतिरिक्त वित्तीय बोझ से राहत मिलती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि समय सीमा के बाद सख्ती जरूरी होती है, ताकि कर व्यवस्था में अनुशासन बना रहे और सभी करदाताओं के लिए समान नियम लागू हो सकें।

कुल मिलाकर, पंजाब सरकार की OTS स्कीम अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। एक ओर जहां बड़ी संख्या में व्यापारी इसका लाभ उठाकर अपने बकाये का निपटान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि 31 मार्च के बाद किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने व्यापारी इस अंतिम अवसर का लाभ उठाते हैं और कितनों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

राजनीति में नई पारी: केसी त्यागी ने थामा RLD का दामन, बदलते समीकरणों के संकेत

जीएनएस)। New Delhi। देश की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है, जहां जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता K. C. Tyagi ने राष्ट्रीय लोक दल (RLD) की सदस्यता ग्रहण कर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी का दामन थामा, जिसमें Jayant Chaudhary की मौजूदगी ने इस फैसले को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया।

यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब देश में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। केसी त्यागी जैसे अनुभवी और लंबे समय से सक्रिय नेता का RLD में शामिल होना न केवल पार्टी के लिए मजबूती का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका आने वाले समय में और प्रभावशाली हो सकती है।

जानकारी के अनुसार, केसी त्यागी ने जदयू से दूरी पहले ही बना ली थी। उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान में हिस्सा नहीं लिया और अपनी सदस्यता का नवीनीकरण भी नहीं कराया। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी छोड़ने के पीछे किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनके इस कदम को राजनीतिक रणनीति और बदलते हालात के संदर्भ में देखा जा रहा है।

केसी त्यागी का राजनीतिक सफर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा है। वे जदयू के गठन के समय से ही पार्टी के साथ जुड़े रहे और संगठन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। साल 2003 में समता पार्टी और जनता दल के विलय के बाद बनी जदयू में उन्होंने महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार जैसे पदों पर कार्य करते हुए पार्टी की विचारधारा और रणनीति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि त्यागी का RLD में जाना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक संकेत भी देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में प्रभाव रखने वाली RLD को इस कदम से अनुभवी नेतृत्व का लाभ मिलेगा, जिससे पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत कर सकती है।

दिल्ली के विट्ठलभाई पटेल हाउस में आयोजित बैठक में केसी त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अपने सिद्धांतों और विचारों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और गरीबों, किसानों तथा कमजोर वर्गों के हितों के लिए पहले की तरह काम करते रहेंगे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि Nitish Kumar के साथ उनका करीब 50 वर्षों का पुराना संबंध है, जो विभिन्न राजनीतिक चरणों से गुजरते हुए मजबूत बना हुआ है। उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से अलग बताते हुए कहा कि विचारधारा और जनहित उनके लिए सर्वोपरि हैं।

RLD नेतृत्व ने भी केसी त्यागी के शामिल होने का स्वागत करते हुए इसे पार्टी के लिए सकारात्मक कदम बताया। जयंत चौधरी ने कहा कि अनुभवी नेताओं के जुड़ने से पार्टी को नई दिशा और मजबूती मिलेगी, जिससे आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।

राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम विपक्षी दलों के बीच नए गठजोड़ और समीकरणों की संभावनाओं को जन्म दे सकता है, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं।

फिलहाल यह स्पष्ट है कि केसी त्यागी का यह फैसला आने वाले समय में राजनीतिक परिदृश्य पर असर डाल सकता है।

वैश्विक मंच से उठी शांति की पुकार: युद्धविराम के लिए बढ़ता दबाव, मानवता को सर्वोपरि रखने की अपील

जीएनएस)। New Delhi। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों और युद्ध की भयावहता के बीच अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की आवाज तेज होती जा रही है। वैश्विक जनसंपर्क समुदाय ने विश्व नेताओं से अपील की है कि वे राजनीतिक और सामरिक मतभेदों से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता दें और तत्काल प्रभाव से युद्धविराम लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।

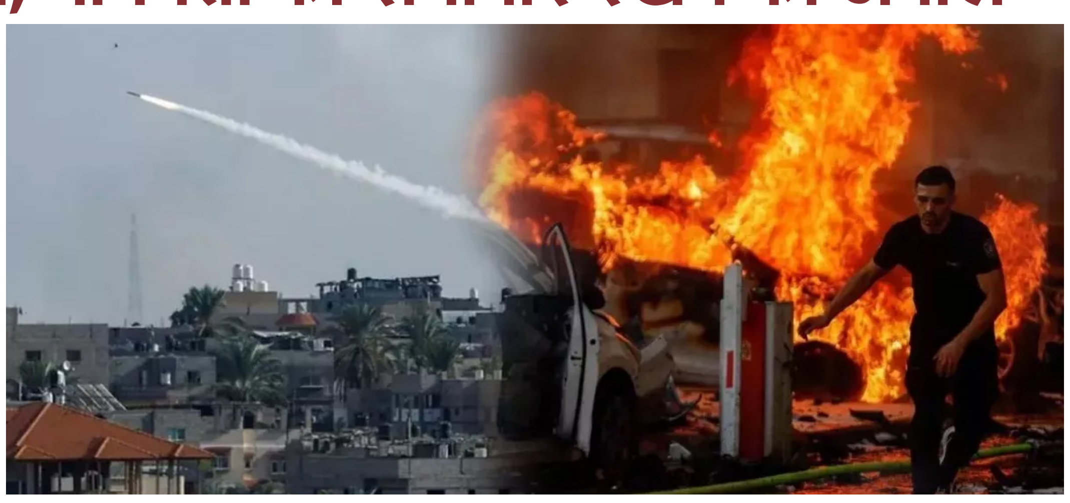

इस अपील में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि युद्ध का प्रभाव केवल सीमित भू-भाग तक नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। चाहे वह मानव जीवन की हानि हो, आर्थिक अस्थिरता हो या पर्यावरणीय संकट—हर स्तर पर युद्ध के दुष्परिणाम गंभीर और दूरगामी होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में चल रहे संघर्षों ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। निर्दोष नागरिकों की मौत, परिवारों का बिखरना और बच्चों का मानसिक आघात—ये सभी ऐसे पहलू हैं, जो आने वाली पीढ़ियों तक असर छोड़ते हैं।

वैश्विक जनसंपर्क समुदाय से जुड़े संगठनों का कहना है कि युद्ध के कारण लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिनके पास न तो सुरक्षित आश्रय है और न ही जीवन की बुनियादी सुविधाएं। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मानवीय संकट का रूप ले चुकी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आर्थिक दृष्टि से भी युद्ध के प्रभाव बेहद गंभीर हैं। पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है। ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर परिवहन, उद्योग और आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, उत्पादन लागत बढ़ती है और अंततः इसका बोझ आम जनता को उठाना पड़ता है।

पर्यावरणीय नुकसान भी युद्ध का एक बड़ा और अक्सर अनदेखा पहलू है। संघर्ष के दौरान होने वाले विस्फोट, हथियारों का इस्तेमाल और बुनियादी ढांचे का विनाश वायु, जल और भूमि प्रदूषण को तेजी से बढ़ाते हैं। इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी प्रभावित होती है, बल्कि आने वाले वर्षों तक पर्यावरण को स्थायी क्षति पहुंचती है। इस पूरे परिदृश्य में कूटनीतिक संबंधों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। देशों के बीच विश्वास की कमी बढ़ती है, जिससे संवाद और सहयोग की संभावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। जब संवाद के रास्ते बंद होते हैं, तो संघर्ष और अधिक जटिल और लंबा हो जाता है।

Dr. Ajit Pathak, जो Public Relations Society of India के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थायी समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्व नेताओं को अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए एक मंच पर आना चाहिए और मानवता के हित में निर्णय लेने चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि आज का समय केवल शक्ति प्रदर्शन का नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और समझदारी का है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसके परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं। वैश्विक समुदाय की यह अपील केवल एक औपचारिक बयान नहीं, बल्कि बढ़ती चिंता और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। यह एक ऐसा संदेश है, जो यह याद दिलाता है कि किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं—वे लोग जो न तो निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं और न ही संघर्ष के कारणों से उनका कोई सीधा संबंध होता है।

इस अपील में विश्व नेताओं से आग्रह किया गया है कि वे तत्काल और स्थायी युद्धविराम के लिए सहमति बनाएं, संघर्ष के मूल कारणों पर गंभीरता से विचार करें और सकारात्मक वार्ता की शुरुआत करें। साथ ही, यह भी कहा गया है कि खुला और पारदर्शी संवाद ही शांति की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। ऐसे में यदि दुनिया को स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है, तो शांति, सहयोग और संवाद को ही प्राथमिकता देनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क समुदाय की यह पहल एक मजबूत संदेश देती है कि अब समय आ गया है जब विश्व नेतृत्व को अपने निर्णयों में मानवता को सर्वोच्च स्थान देना होगा। यही वह रास्ता है, जो न केवल वर्तमान संकट को कम कर सकता है, बल्कि भविष्य के लिए एक स्थायी और शांतिपूर्ण दुनिया की नींव भी रख सकता है।

इच्छामृत्यु की अनुमति के बावजूद बाकी सवाल

> "इच्छामृत्यु के विरोध में जो तर्क है, उसके अनुसार जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप गलत है। इच्छामृत्यु के अधिकार का दुरुपयोग होने का खतरा भी है। डॉक्टर 'किलर' बन जाएंगे। कोमा में पड़े लोगों को व्यर्थ समझ लिया जाएगा।

ग़ाज़ियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परोक्ष इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) के लिए एम्स दिल्ली के पैलिएटिव केयर विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। इच्छामृत्यु की प्रक्रिया को पूरा होने में कई सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि इसमें कई चरण शामिल हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया की व्यावहारिकता से जुड़े कई सवाल अभी हैं, पर अब बहस एक्टिव इच्छामृत्यु यानी दवा देकर या किसी दूसरे तरीके से मृत्यु देने पर भी होगी। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि संसद इस विषय पर कानून बनाए। 2018 और 2026 के फैसलों के बावजूद संसद ने अभी तक समग्र कानून नहीं बनाया। कोर्ट ने कई बार विधायिका से कानून बनाने की अपील की है।

पैलिएटिव केयर में ऐसी चिकित्सा देखभाल होती है, जिसका उद्देश्य गंभीर या असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीज को आराम देना और बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के बजाय मरीज के दर्द, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, बेचैनी या अन्य शारीरिक-मानसिक परेशानियों को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। सक्रिय इच्छामृत्यु मृत्यु का एक नया कारण उत्पन्न करती है; निष्क्रिय इच्छामृत्यु पहले से ही चल रही प्राकृतिक मृत्यु में बाधा को दूर करती है। एक मृत्यु का कारण बनती है; दूसरी मृत्यु को स्वाभाविक रूप से होने देती है। एक्टिव इच्छामृत्यु यानी दवा या किसी दूसरे तरीके से मौत देना पूरी तरह अवैध है। प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीने के अधिकार' में 'गरिमापूर्ण मरने का अधिकार' शामिल है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने हां कहा है, लेकिन सीमित परिस्थितियों में। हरीश राणा केस के फैसले के बाद भी, यह बहस अभी अपूर्ण है। इच्छामृत्यु के विरोध में जो तर्क है, उसके अनुसार जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप गलत है। इच्छामृत्यु के अधिकार का दुरुपयोग होने का खतरा भी है। डॉक्टर 'किलर' बन जाएंगे। कोमा में पड़े लोगों को व्यर्थ समझ लिया जाएगा। कैथलिक चर्च, कई हिंदू संगठन और इस्लामी विद्वान इसे जीवन के खिलाफ मानते हैं।

यदि इसे लागू भी किया जाए, तो देश में अच्छी पैलिएटिव केयर बहुत कम है, इसलिए कई लोग इच्छामृत्यु को 'आखिरी विकल्प' मानते हैं। इस समय बहस का केंद्र बिंदु यही है कि पैसिव इच्छामृत्यु को और सुगम बनाया जाए या नहीं, जबकि एक्टिव इच्छामृत्यु को वैध करने की मांग अभी बहुत कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल असंभव रिकवरी वाले केस में, सख्त मेडिकल बोर्ड और न्यायिक देखरेख के साथ ही इसकी अनुमति देने पर विचार संभव है। बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि असली समाधान बेहतर पैलिएटिव केयर की व्यवस्था को मजबूत करने में है, न कि जल्दबाजी में एक्टिव इच्छामृत्यु को वैध करने में।

वर्ष 2013 में चंडीगढ़ में एक हादसे में चौथी मंजिल से गिरने के बाद से हरीश अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हुए हैं, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गत 11 मार्च को उनके मामले में, पैसिव इच्छामृत्यु की अनुमति देकर भारत में पहली बार इस अधिकार के व्यावहारिक इस्तेमाल की अनुमति दी है। अदालत ने 2018 में इसे संवैधानिक अधिकार मान लिया था।

हरीश राणा के माता-पिता की याचिका को, पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने और फिर उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। 2025 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और यह निर्णय सुनाया। यह मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित और 2023 में सरलीकृत कानूनी ढांचे और इन दिशानिर्देशों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर करता है। विशेषज्ञ सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच अंतर पर और भारत में मजबूत देखभाल अवसंरचना की आवश्यकता पर भी चर्चा करते हैं। जटिल समस्या यह नहीं है कि कानून किस बात की अनुमति देता है, बल्कि यह है कि रोगी, जब स्वयं बोलने में असमर्थ हो, तो कौन और किस आधार पर निर्णय कर सकता है। स्वस्थ दिमाग वाला वयस्क किसी भी चिकित्सा उपचार को अस्वीकार कर सकता है, और चिकित्सक को उस अस्वीकृति का सम्मान करना होता है। ज्यादा मुश्किल मामला अनैच्छिक मृत्यु का है। ऐसा रोगी जो स्थायी रूप से कोमा में है, जिसका अस्तित्व पूरी तरह से चिकित्सा तकनीक पर निर्भर है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की दो-न्यायाधीशों की पीठ के इस फैसले को पूरी तरह से समझने के लिए, 2011 में अरुणा शानबाग के मामले से लेकर 2018 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में संवैधानिक फैसले तक की कड़ी को जोड़ना आवश्यक है। अरुणा रामचंद्र शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में नर्स थीं, जिनका 27 नवंबर, 1973 की रात को एक वार्ड अटेंडेंट ने गला घोंट दिया था। गला घुटने से उनके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक गई थी। लगभग 42 वर्षों तक वे उसी अस्पताल में अचेत अवस्था में रहीं और 2015 में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। 2011 में, सर्वोच्च न्यायालय में उनकी जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की गई थी। दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में याचिका खारिज कर दी, लेकिन भारतीय कानून में पहली बार परोक्ष इच्छामृत्यु के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए। अदालत ने दयामृत्यु को अस्वीकार करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया कि मुंबई के केईएम अस्पताल की नर्सें और अन्य कर्मचारी अरुणा को मरने देना नहीं चाहते। इन नर्सों ने 37 साल से अरुणा की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। नर्सों के जीवन में अरुणा का एक मतलब हो गया था, जो उनकी एकता की कड़ी थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2018 के फैसले में 2011 के फैसले की संरचनात्मक खामियों को उजागर किया। 2018 में कॉमन कॉज़ मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी शामिल है और असाध्य कोमा में पड़े रोगी के परिवार के सदस्य जीवन रक्षक उपचार बंद करने के लिए अदालत से अनुमति मांग सकते हैं। पीठ ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित किए—दो स्वतंत्र चिकित्सा बोर्ड, परिवार की अनिवार्य सहमति और 30 दिन की पुनर्विचार अवधि—और अग्रिम चिकित्सा निर्देशों को मान्यता दी, जिनके द्वारा कोई व्यक्ति सक्षम रहते हुए भी अपने जीवन के अंतिम समय की प्राथमिकताओं को दर्ज कर सकता है।

राणा परिवार ने जब 2024 में अपने बेटे को जीवित रखने वाली फीडिंग ट्यूब हटाने की अनुमति मांगने के लिए पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, तो अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, हरीश स्वतंत्र रूप से सांस लेकर बिना चिकित्सकीय सहायता के स्वयं को जीवित रख रहा है, इसलिए फीडिंग ट्यूब जीवन रक्षक प्रणाली को नहीं हटाया जा सकता। अब 11 मार्च के फैसले में इसे बदल दिया गया। न्यायालय ने अब यह माना है कि चिकित्सकीय सहायता प्राप्त पोषण को हटाना रोगी को भूखा रखना नहीं है। यह एक ऐसे हस्तक्षेप को हटाना है जिसका कोई चिकित्सीय उद्देश्य नहीं रह गया है।

शानबाग से लेकर कॉमन कॉज़ और हरीश राणा तक का सैद्धांतिक विकास 15 वर्षीय यात्रा है, जो कुछ नए सवाल खड़े कर रही है। 11 मार्च का फैसला सिद्धांत तो स्थापित कर देता है, जो विधि आयोग की 2006 की 196वीं रिपोर्ट में कानून की सिफारिश के बाद से ही अनसुलझा है।

संपादकीय

सवाल वही, सच्चाई नई: गैस की कहानी कई परतों में

एक साधारण-सा सवाल—गैस है क्या?—आज के समय में इतना असाधारण क्यों लगने लगा है, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। यह वही शब्द है जो कभी घर की रसोई से जुड़ा था, कभी डॉक्टर की पर्ची में दिखता था, और कभी औद्योगिक हादसों की खबरों में डर पैदा करता था। लेकिन आज यह एक ऐसा प्रश्न बन गया है, जो केवल जानकारी नहीं मांगता, बल्कि व्यवस्था, भरोसे और हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करता है। गैस का अर्थ समझना हो तो सबसे पहले हमें अपने ही शरीर की तरफ देखना होगा। पेट में गैस बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब यह बढ़ जाती है, तो असामान्य हो जाती है। इंसान बेचैन हो जाता है, हर छोटी-सी तकलीफ बड़ी बीमारी का संकेत लगने लगती है। कई बार तो यह भ्रम इतना गहरा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसे दिल से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो गई है। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद जब जवाब मिलता है कि "यह सिर्फ गैस है," तो राहत भी मिलती है और थोड़ी हैरानी भी। यानी एक ऐसी चीज जो दिखती नहीं, लेकिन असर गहरा छोड़ती है। इसी तरह समाज में भी कई तरह की "गैस" मौजूद है। एक वह जो उद्योगों से निकलती है और जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो त्रासदी का रूप ले लेती है। ऐसे हादसे हमें बार-बार यह याद दिलाते हैं कि विकास की दौड़ में सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितना महंगा पड़ सकता है। यह केवल तकनीकी चूक नहीं होती, बल्कि यह उस सोच की कमी को भी दर्शाती है जिसमें इंसान की जान से ज्यादा उत्पादन और मुनाफा अहम हो जाता है। फिर एक और खामोश लेकिन घातक रूप है—गटर की गैस। यह वह सच्चाई है, जिसके बारे में समाज जानता तो है, लेकिन स्वीकारना नहीं चाहता। सफाईकर्मी जब सीवर में उतरते हैं, तो उनके पास न पर्याप्त सुरक्षा होती है और न ही कोई ठोस गारंटी कि वे वापस सुरक्षित निकलेंगे। हर साल कई जानें इस अदृश्य खतरे की भेंट चढ़ जाती हैं, लेकिन इन घटनाओं को अक्सर सामान्य मान लिया जाता है। जैसे यह एक तयशुदा जोखिम हो, जिसे बदलना हमारे बस में नहीं। इन सभी रूपों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस गैस की होती है, वह है रसोई में इस्तेमाल होने वाली गैस। यही वह गैस है जो हर घर की जरूरत है, जो हर दिन के जीवन को चलाती है। लेकिन जब इसी गैस के बारे में यह सवाल उठने लगे कि "क्या यह उपलब्ध है?", तो मामला केवल एक सुविधा का नहीं, बल्कि एक बड़े संकट का संकेत बन जाता है। अचानक लोग चिंतित हो जाते हैं, घरों में अनिश्चितता फैल जाती है, और बाजार में हलचल शुरू हो जाती है। जब कोई कहता है कि गैस नहीं है, तो इसका असर केवल एक खबर तक सीमित नहीं रहता। यह सीधे उस चूल्हे तक पहुंचता है, जहां हर दिन भोजन तैयार होता है। यह उस परिवार तक जाता है, जिसकी दिनचर्या इस पर निर्भर है। और यह उस छोटे व्यवसाय तक भी असर डालता है, जो इसी के सहारे चलता है। रसोई की गैस केवल ईंधन नहीं है, यह जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे माहौल में अलग-अलग तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कमी है, कुछ कहते हैं कि सब सामान्य है। एक तरफ आम लोग अपनी परेशानी बता रहे होते हैं, दूसरी तरफ आधिकारिक बयान स्थिति को नियंत्रित और संतुलित दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वह जगह है जहां सच्चाई और बयानबाजी के बीच की दूरी साफ नजर आने लगती है। यह सवाल भी उठता है कि क्या यह केवल आपूर्ति की समस्या है, या इसके पीछे कोई गहरी संरचनात्मक खामी है। क्या यह केवल अस्थायी स्थिति है, या यह उस व्यवस्था की कमजोरी का संकेत है जो समय पर जरूरतों को पूरा करने में असफल हो रही है? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या इस समस्या को स्वीकारने और सुलझाने की ईमानदार कोशिश हो रही है, या इसे केवल शब्दों के सहारे ढकने की कोशिश की जा रही है? गैस का यह सवाल धीरे-धीरे एक व्यापक प्रतीक बनता जा रहा है। यह केवल एक वस्तु की उपलब्धता का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भरोसे का सवाल है। जब लोगों को बार-बार यह महसूस होने लगे कि जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है, उसमें फर्क है, तो विश्वास कमजोर होने लगता है। और जब विश्वास कमजोर होता है, तो कोई भी छोटी समस्या बड़ी लगने लगती है।

इस पूरे परिदृश्य में एक और पहलू भी है—हमारा नजरिया। हम अक्सर समस्याओं को केवल उनके बाहरी रूप में देखते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी परतों को समझने की कोशिश नहीं करते। गैस की कमी हो या किसी और चीज की, यह केवल एक संकेत हो सकता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। लेकिन जब तक हम इसे केवल एक तात्कालिक समस्या मानते रहेंगे, तब तक स्थायी समाधान नहीं मिल पाएगा। आखिर में, यह कहना गलत नहीं होगा कि "गैस है क्या?" यह सवाल अपने आप में एक आईना है।

प्रेरणा

श्राप या सच: डर, धोखे और विश्वास की उलझी कहानी

नाले के उस पार की बस्ती में कदम रखते ही शर्मा जी को ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। उधर उनकी कॉलोनी की साफ-सुथरी सड़कें, व्यवस्थित घर और शांत माहौल था, और इधर कच्ची गलियां, टूटी झुग्गियां और हर तरफ बिखरी हुई जिंदगी की जद्दोजहद। लेकिन आज उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी—हरिहर बाबा का श्राप। क्या सच में कोई श्राप इतना प्रभावी हो सकता है कि किसी का पूरा परिवार संकट में पड़ जाए?

सुबह की घटना बार-बार उनके मन में घूम रही थी। एक साधु का यूं अचानक उनके घर आना, खुद को "हरिहर बाबा" बताना और फिर दान की मांग करना—यह सब पहले तो सामान्य ही लगा था। लेकिन जब उसने दो रुपये के सिक्के पर नाराजगी जताई और बड़े दान की बात की, तभी से माहौल बदल गया था। उसके शब्दों में जो आग्रह था, वह धीरे-धीरे दबाव में बदलने लगा था। और जब उनके बेटे ने उसका विरोध किया, तो वह आग्रह गुस्से में और फिर धमकी में बदल गया।

"श्राप" शब्द जैसे घर की दीवारों में गूंजने लगा था। बाबा के जाते ही घर में एक अजीब-सी खामोशी छा गई थी। मां के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनकी आंखों में वह विश्वास था, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था—कि साधु-संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के रूप होते हैं। और अगर उनका अपमान हो जाए, तो उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है।

शर्मा जी इस सोच को समझते थे, लेकिन उससे सहमत नहीं थे। उनके लिए यह सब अंधविश्वास था। उन्होंने अपनी मां को समझाने की कोशिश की कि आज के समय में ऐसे श्रापों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन डर तर्क से ज्यादा मजबूत होता है। मां बार-बार यही कह रही थी कि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? अगर बाबा का श्राप सच हो गया तो?

इसी डर ने शर्मा जी को यहां तक खींच लाया था। वे खुद इस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मां की चिंता ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वे उस बाबा को ढूंढें और किसी तरह उससे माफी मंगवाएं। यह एक अजीब स्थिति थी—जहां एक पढ़ा-लिखा, समझदार इंसान भी किसी और के डर के कारण उस चीज की तलाश में निकल पड़ा था, जिस पर वह खुद विश्वास नहीं करता।

नाले के पास बैठे भिखारियों से पूछताछ करने के बाद जब उन्हें पता चला कि हरिहर बाबा झुग्गियों में रहता है, तो उनके मन में एक और सवाल उठा। अगर वह इतना बड़ा बाबा है, तो इस हालत में क्यों रहता है? लेकिन उन्होंने इस सवाल को नजरअंदाज किया और बताए गए रास्ते पर चल पड़े।

झुग्गी के सामने पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछने पर जो सच्चाई सामने आई, उसने उनके सारे विचारों को झकझोर कर रख दिया। हरिहर कोई बाबा नहीं था, बल्कि एक साधारण आदमी था, जिसकी अपनी जिंदगी ही परेशानियों से भरी हुई थी। उसके बच्चे बीमार थे, पत्नी अस्पताल में थी, और वह खुद नशे में डूबा रहता था।

सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जिस व्यक्ति ने सुबह उनके घर आकर श्राप दिया था, वही कुछ समय पहले एक कोठी में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसने एक महिला को गहने दुगने करने का लालच दिया, और जब मौका मिला, तो गहने लेकर भागने की कोशिश की। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह पकड़ा गया, लोगों ने उसे पीटा, और उसकी टांग तक तोड़ दी गई।

यह सुनकर शर्मा जी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक अजीब-सी शांति भी थी और एक गहरी सोच भी। जिस व्यक्ति के श्राप से उनका परिवार डरा हुआ था, वह खुद अपनी हरकतों की सजा भुगत रहा था। जिस "शक्ति" का वह दावा कर रहा था, वह असल में केवल एक भ्रम था, जिसे वह लोगों के डर का फायदा उठाकर इस्तेमाल कर रहा था।

घर लौटते समय शर्मा जी के कदम पहले से हल्के थे। उन्हें अब किसी बाबा से माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक सवाल उनके मन में जरूर था—अगर यह सच्चाई उन्हें न पता चलती, तो क्या होता? क्या वे भी उसी डर में जीते रहते, और हर छोटी-बड़ी घटना को उस श्राप से जोड़ते रहते?

घर पहुंचकर उन्होंने पूरी बात बताई। मां पहले तो चुप रही, फिर धीरे-धीरे उनके चेहरे पर भी समझ की झलक आने लगी। डर पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें कमी जरूर आई थी। यह एक लंबी प्रक्रिया थी—सालों से जमे विश्वास को एक ही दिन में बदलना आसान नहीं होता।

यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं है। यह उस समाज की कहानी है, जहां आज भी डर और अंधविश्वास का गहरा असर है। जहां लोग अपनी परेशानियों का हल तर्क और समझ में नहीं, बल्कि किसी चमत्कार या श्राप में ढूंढते हैं। और जहां कुछ लोग इसी डर का फायदा उठाकर दूसरों को धोखा देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बदलाव संभव है। जब सच्चाई सामने आती है, तो डर अपने आप कम होने लगता है। जब लोग सवाल पूछने लगते हैं, तो जवाब भी बदलने लगते हैं। और जब विश्वास तर्क से टकराता है, तो धीरे-धीरे एक नई समझ जन्म लेती है।

आखिर में, यह तय करना हर व्यक्ति के हाथ में है कि वह किस पर विश्वास करता है—डर पर या सच्चाई पर। क्योंकि श्राप से ज्यादा ताकतवर चीज है हमारी सोच। अगर सोच मजबूत हो, तो कोई भी श्राप असर नहीं कर सकता। लेकिन अगर सोच डर से घिरी हो, तो बिना किसी कारण के भी जीवन एक श्राप जैसा लगने लगता है।

शर्मा जी के लिए यह एक सीख थी—कि हर आवाज जो खुद को सच कहती है, वह सच नहीं होती। और हर डर जो मन में बैठ जाता है, वह वास्तविक नहीं होता। असली ताकत उस समझ में है, जो हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती है।

भगत सिंह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सावरकर की करते थे तारीफ

23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। देश इस दिन को 'बलिदान दिवस' के रूप में स्मरण करता है। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। किंतु समय के साथ इस बलिदान की व्याख्या, अक्सर एक विशेष वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती रही।

पाठ्य-पुस्तकों, लेखों और सार्वजनिक विमर्श में विशेष रूप से भगत सिंह को एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ, जबकि विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारी को प्रायः सांप्रदायिक खांचे में रखकर प्रस्तुत किया गया। परंतु जब इतिहास के पन्नों को ध्यान से देखा जाता है तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। वास्तव में भगत सिंह और सावरकर, दोनों ही भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में देखते थे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से प्रेरित थे। एक-दूसरे के विचारों और कार्यों का उन पर गहरा प्रभाव था। वीर सावरकर और भगत सिंह के संबंधों से जुड़े कई ऐतिहासिक तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं। प्रसिद्ध मराठी इतिहासकार य. दि. फड़के के अनुसार, भगत सिंह सावरकर को बतौर क्रांतिकारी एक आदर्श के रूप में देखते थे। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक '1857 का स्वातंत्र्य समर' का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया और उसे क्रांतिकारियों के बीच प्रचारित भी किया। (संदर्भ- शोध सावरकरांचा, य. दि. फडके, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे)

सावरकर की एक अन्य पुस्तक 'हिंदूपदपादशाही' का भी भगत सिंह पर प्रभाव दिखाई देता है। अपनी जेल डायरी में उन्होंने इस पुस्तक से कई उद्धरण दर्ज किए हैं। उदाहरण के लिए-

'बलिदान की सराहना केवल तभी की जाती है जब बलिदान वास्तविक हो या सफलता के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। लेकिन जो बलिदान अंततः सफलता की ओर नहीं ले जाता है, वह आत्मघाती है और इसलिए मराठा युद्धनीति में उसका कोई स्थान नहीं था।' (हिंदूपदपादशाही, पृष्ठ 257) और साथ ही 'वीरता के कार्य किए बिना, वीरता का प्रदर्शन किए बिना और साहस के साथ इतिहास रचे बिना इतिहास लिखना हमारे समय का एक बुरा स्वप्न है। वीरता को वास्तविकता में बदलने का अवसर न मिलना हमारे लिए खेद का विषय है।' (हिंदूपदपादशाही, पृष्ठ 265-266)

भगत सिंह के लेखन में भी सावरकर के प्रति सम्मान स्पष्ट दिखाई देता है। कोलकाता से निकलने वाले साप्ताहिक 'मतवाला' के 15 और 22 नवंबर 1924 के अंक में उनका एक लेख 'विश्व प्रेम' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसमें वे लिखते हैं- 'विश्वप्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी, कट्टर अराजकतावादी कहने में हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं समझते - वही वीर सावरकर। विश्वप्रेम की तरंग में आकर वे घास पर चलते-चलते रुक जाते कि कहीं कोमल घास पैरों तले न मसली जाए।'

यह लेख बलवंत सिंह के छद्म नाम से लिखा गया था। (संदर्भ- भगतसिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज, पृष्ठ संख्या 93, पुनर्मुद्रण मई 2019, राहुल फाउंडेशन, लखनऊ)। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस समय भगत सिंह ने यह लेख लिखा, उस समय सावरकर रत्नागिरी में नजरबंद थे और उन पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ था।

इसी प्रकार भगत सिंह ने 'किरती' नामक प्रकाशन में मार्च 1928 से अक्टूबर 1928 तक 'आजादी की भेंट शहादतें' शीर्षक से एक लेखमाला लिखी। इसमें कर्जन वायली की हत्या करने वाले क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा और सावरकर का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं- 'स्वदेशी आंदोलन का असर इंग्लैंड तक भी पहुंचा और वहां पहुंचते ही श्री सावरकर ने 'इंडिया हाउस' नामक सभा की स्थापना की। मदनलाल भी उसके सदस्य बने एक दिन रात को श्री सावरकर और मदनलाल ढींगरा बहुत देर तक मशवरा करते रहे। अपनी जान तक दे देने के साहस की परीक्षा लेने के लिए सावरकर ने मदनलाल से जमीन पर हाथ रखने को कहा और उनके हाथ पर सुआ गाड़ दिया, लेकिन उस पंजाबी वीर ने आह तक नहीं भरी। सुआ निकाल लिया गया। दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वे एक-दूसरे के गले लग गए। आहा, वह समय कितना सुंदर था हम दुनियादार लोग क्या जानें कि देश और कौम के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वे लोग कितने ऊंचे, कितने पवित्र और कितने पूजनीय होते हैं!' (संदर्भ- भगतसिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज, पृष्ठ संख्या 166-168)

23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, तब सावरकर ने उनकी स्मृति में एक कविता लिखी-

'हा, भगत सिंह, हाय हा!
चढ़ गया फांसी पर तू वीर हमारे लिए,
हाय हा!
राजगुरु तू, हाय हा!
वीर कुमार, राष्ट्रसमर में हुआ शहीद,
हाय हा! जय जय हा! '

रत्नागिरी में सावरकर के घर हमेशा भगवा झंडा फहराया जाता था किंतु भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान के अगले दिन काला झंडा फहराया गया। यह उनके प्रति सावरकर की श्रद्धांजलि का प्रतीक था। भगत सिंह के साथियों- जैसे भगवतीचरण वोरा ने भी अपने लेखन में सावरकर और उनके साहित्य के प्रभाव का उल्लेख किया है। इन संदर्भों का विस्तृत विवरण 'भगतसिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज' में है।

अभियान

तुलसी की छांव में लिखी नई किस्मत: कामदा एकादशी की भक्ति से बदलता जीवन

चैत्र मास की पवित्र हवाएं जब धरती को स्पर्श करती हैं, तो वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिक कंपन महसूस होने लगता है। यही वह समय होता है जब कामदा एकादशी का आगमन होता है, और यह दिन केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला अवसर बन जाता है। वर्ष 2026 में 29 मार्च को पड़ने वाली यह एकादशी अपने भीतर अनगिनत संभावनाएं समेटे हुए है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त पूरे मन से साधना करते हैं, और इसी साधना में तुलसी चालीसा का पाठ एक दिव्य सेतु बन जाता है, जो मनुष्य को उसके भाग्य से जोड़ देता है।

भक्ति की सबसे सुंदर विशेषता यह है कि यह किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती। यह दिल की गहराइयों से निकलती है और वहीं जाकर ईश्वर से मिलती है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान प्राप्त है। उन्हें केवल एक पौधा नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब कोई भक्त तुलसी के सामने दीप जलाता है, जल अर्पित करता है और श्रद्धा से चालीसा का पाठ करता है, तो वह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं करता, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है।

एक छोटे से कस्बे में गीता नाम की एक युवती रहती थी। उसके जीवन में संघर्ष जैसे स्थायी रूप से बस गया था। पढ़ाई में मेहनती होने के बावजूद उसे बार-बार असफलता मिल रही थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, और हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा था। एक दिन उसकी दादी ने उसे कामदा एकादशी का महत्व बताया और कहा कि इस दिन तुलसी माता की पूजा और चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं।

गीता ने पहले इसे एक साधारण सलाह समझा, लेकिन जब उसने अपने जीवन की स्थिति पर नजर डाली, तो उसे लगा कि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने पूरे मन से व्रत रखा, तुलसी माता के सामने बैठकर चालीसा का पाठ किया और मन ही मन अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर एक अजीब-सी शांति जरूर आई। उसने इसे एक संकेत माना और अपनी भक्ति को जारी रखा।

समय के साथ गीता की सोच बदलने लगी। वह पहले जहां असफलता से डरती थी, अब उसे एक सीख के रूप में देखने लगी। धीरे-धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। उसे एक अच्छी नौकरी मिली, परिवार की स्थिति सुधरने लगी और सबसे महत्वपूर्ण—उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। उसे महसूस हुआ कि भक्ति केवल भगवान से कुछ मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें भीतर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया है।

इसी तरह एक और कहानी है राजेश की, जो एक व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था—धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा। लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। व्यापार में लगातार उतार-चढ़ाव और मानसिक तनाव ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया था। एक दिन उसने एक संत से अपनी समस्या बताई। संत ने उसे कामदा एकादशी के दिन तुलसी चालीसा का पाठ करने की सलाह दी। राजेश ने इसे अपनाया, लेकिन उसके मन में संदेह भी था। उसने व्रत रखा, पूजा की और चालीसा का पाठ किया। धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा है। वह पहले जहां हर छोटी समस्या पर घबरा जाता था, अब उसे धैर्य से संभालने लगा। उसके व्यापार में भी स्थिरता आने लगी और उसका मन शांत होने लगा। उसे समझ में आया कि असली सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि मन की शांति में है।

कामदा एकादशी का महत्व केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए। जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, तो हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह ऊर्जा धीरे-धीरे हमारे आसपास के वातावरण को भी बदलने लगती है।

एक वृद्ध दंपत्ति की कहानी भी इस संदर्भ में बहुत प्रेरणादायक है। वे दोनों अपने बच्चों से दूर अकेले रहते थे। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी साथ और सहारे की, लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं। एक दिन उन्होंने कामदा एकादशी का व्रत रखने और तुलसी चालीसा का पाठ करने का निर्णय लिया।

उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से यह साधना शुरू की। धीरे-धीरे उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। उनके बच्चे उनसे मिलने आने लगे, उनके बीच का संवाद बढ़ा और उनके जीवन में फिर से खुशियों का आगमन हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि भक्ति केवल ईश्वर से जुड़ने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत बनाती है।

आज के आधुनिक युग में, जहां लोग तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, कामदा एकादशी हमें ठहरकर सोचने का अवसर देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक सुख-सुविधाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का भी नाम है। तुलसी चालीसा का पाठ इस संतुलन को बनाए रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका है।

भक्ति का मार्ग हमेशा धैर्य और विश्वास की मांग करता है। यह कोई जादू नहीं है, जो तुरंत परिणाम दे दे। लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे हमारे जीवन को बदल देती है। जब हम नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करते हैं और चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारे भीतर की नकारात्मकता दूर होने लगती है और सकारात्मकता का संचार होता है।

अंततः, कामदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। यह हमें अपने भीतर झांकने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का अवसर देती है। जब हम इस दिन पूरे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हमें केवल भौतिक लाभ ही नहीं मिलता, बल्कि एक गहरी शांति और संतोष भी प्राप्त होता है।

इसलिए यदि जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, यदि बार-बार असफलता मिल रही है या मन अशांत है, तो इस कामदा एकादशी पर तुलसी चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का एक माध्यम है। हो सकता है कि आपको तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत जरूर होगी। और यही बदलाव धीरे-धीरे आपको उस स्थान तक ले जाएगा, जहां सुख, शांति और समृद्धि आपका इंतजार कर रहे हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा अमरेली जिले के नागरिकों को 707 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं की भेंट

▶▶ मुख्यमंत्री ने अमरेली जिले की आधारभूत सुविधाओं को वेग देने वाले 681.78 करोड़ रुपए के 14 विकास कार्यों का शिलान्यास : जनसुख में वृद्धि करने वाले 25.23 करोड़ रुपए के 10 विकास कार्यों का लोकार्पण किया

▶▶ मुख्यमंत्री ने अमरेली एपीएमसी में विशाल जनसभा को संबोधित कर 12 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख वर्ग फुट में निर्मित 'विराट' तकती का लोकार्पण किया

▶▶ मुख्यमंत्री ने अमरेली जिले के विकास के लिए जो मांगा गया वह दिया है : ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया

▶▶ अमरेली जिले के विकास को नई दिशा; राधेश्याम माचियाळा बायपास का 272 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा; मार्ग एवं भवन पंचायत तथा राज्य विभाग के लगभग 662 करोड़ रुपए के 11 कार्यों का शिलान्यास हुआ

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ अमरेली जिले में औद्योगिक विकास के लिए नई तत्परता : सौराष्ट्र रीजनल वाइब्रेंट समिट में अमरेली जिले के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं में निवेश हेतु 36,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं

▶▶ अमरेली जिले के विकास के लिए राज्य सरकार उदारतापूर्वक आवश्यक धन उपलब्ध कराएगी

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से पूरे देश में गुजरात राज्य वित्तीय प्रबंधन में शीर्ष स्थान पर

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भविष्य में पानी का संकट न आए इसके लिए अभी से आवश्यक योजना बनाई गई है

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को अमरेली जिले की आधारभूत सुविधाओं को वेग देने वाले तथा जनकल्याण के 700 करोड़ रुपए से अधिक के 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने अमरेली जिले की प्रगति को नई दिशा देने वाले जनहितोन्मुखी विकास कार्यों की भेंट दी और अमरेली एपीएमसी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही किसानों के उत्पादों के संरक्षण के लिए 12 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 लाख वर्ग फुट के 'विराट' तकती का अनावरण कर लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अध्यक्ष पद से संबोधित करते हुए कहा कि अमरेली जिले के विकास के लिए राज्य सरकार उदारतापूर्वक आवश्यक धन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए उन्होंने जिले के विकास कार्यों का सुव्यवस्थित नियोजन तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने की सावधानी रखते हुए विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की अपील की।

उन्होंने आगे कहा कि अमरेली जिले में औद्योगिक विकास के लिए नई तत्परता देखी जा रही है। हाल ही में आयोजित सौराष्ट्र रीजनल वाइब्रेंट समिट में अमरेली जिले के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए लगभग 36,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। इसके अलावा एक नई जीआईडीसी भी मंजूर की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने टीम बनाकर सुव्यवस्थित विकास कार्यों की योजना बनाई है, जिसके परिणामस्वरूप इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज के सुदूरवर्ती व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध विकास आवश्यक है तथा उन्होंने शहरों में जैसी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं; वैसी ही सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराने पर बल दिया।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात राज्य वित्तीय प्रबंधन में देश में शीर्ष स्थान पर है, जिसके परिणामस्वरुप विकास का कोई भी कार्य अटकता नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को जमीन पर उतारने के लिए पूर्ण रूप से मदद के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों में मौजूद उत्साह की सराहना की। अमरेली जिले के लोग पानी की समस्या से भली-भांति परिचित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भविष्य में जल संकट न आए, इसके लिए अभी से आवश्यक योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही 'कैच द रेन' अभियान के तहत वर्षा जल को जमीन में उतारने के कार्य भी किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि वर्षा जल संग्रहण के लिए विधायकों को प्रति वर्ष 50 लाख रुपए की अलग से ग्रांट भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए विकसित गुजरात की मंशा को चरितार्थ करने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर ऊर्जा एवं कानून राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार ने अमरेली जिले को उदारतापूर्वक विकास कार्यों की भेंट दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना पूरे विश्व में की गई है और उनके नेतृत्व में उकेरी गई विकास यात्रा को मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के करकमलों से लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का शिलान्यास होगा। साथ ही अमरेली रिवरफ्रंट के लिए 50 करोड़ रुपए की योजना को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

अमरेली में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए विकास कार्यों की भेंट के तहत आगामी समय में लाठी रोड के रेलवे फाटक पर 95 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज तैयार होगा। बाबापुर मार्ग पर 35 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज ऑफ नेचुरल फार्मिंग बनाया जाएगा। वडिया शहर और तहसील को पहला विज्ञान कॉलेज की सुविधा मिली है। युवाओं के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र और 16 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किए जा रहे हैं। गत बजट में लाइब्रेरी के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हाल ही में वरसडा में 35 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति कार्यों का लोकार्पण किया गया है। कुछ समय पहले राज्य में हुए बेमौसम बारिश के चलते मुख्यमंत्री ने तुरंत किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का पैकेज घोषित कर तत्काल सहायता जमा करवाई थी।

अमरेली एपीएमसी पधारे निकोल के विधायक श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई और मुख्यमंत्री द्वारा आगे बढ़ाई जा रही निरंतर विकास यात्रा के अंतर्गत सौराष्ट्र की मूल समस्या तथा पानी और सिंचाई की विकास गाथा का वर्णन किया। उन्होंने आगे कहा कि आज प्रधानमंत्री ने नर्मदा के पानी को 'सभी की योजना' के कैनाल नेटवर्क और पाइपलाइन द्वारा सौराष्ट्र की माताओं - बहनों के घर-घर तक पहुंचाया है। इस कड़ी के अंतर्गत 1 लाख से अधिक चेकडैम का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने देश की 10 करोड़ माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे प्रदान किए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। इस पूरे विकास का श्रेय प्रधानमंत्री को अर्पित है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को मंत्रियों और विधायकों द्वारा टावर की प्रतिकृति भेंट कर सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आंबरडी सफारी पार्क की प्रतिकृति देकर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। टीम अमरेली द्वारा राम मंदिर और विकास गाथा को दर्शाती प्रतिकृति भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया।

इस अवसर पर अमरेली में निकोल के विधायक श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा का टीम अमरेली की ओर से 1,11,111 नोटबुक्स देकर स्वागत किया गया। श्री विश्वकर्मा ने इन नोटबुक्स को जरूरतमंद विद्यार्थियों में वितरित करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम के अंत में एनएलआरएम योजना की लाभार्थी महिलाओं को चेक वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबियों की प्रतीकात्मक भेंट दी गई। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को आर्थिक प्रोत्साहन के चेक दिए गए। 69वीं राष्ट्रीय स्तर की अंडर-19 स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता में विजेता टीमों (लड़के और लड़कियां) को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री तथा महानुभावों ने दिव्यांगजनों को ई-ट्राइसाइकिल प्रदान कर उन्हें प्रस्थान करवाया।

मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व सांसद श्री भरतभाई सुतरिया, विधायक श्री महेशभाई कसवाला तथा सहकारी अग्रणी श्री पी.पी. सोजित्रा ने प्रासंगिक संबोधन किया। जिला कलेक्टर श्री विकल्प भारद्वाज द्वारा आभार विधि की गई।

इस अवसर पर विधायक श्री हीराभाई सोलंकी, श्री जे.वी. काकडिया, श्री जनकभाई तळाविया, श्री महेशभाई कसवाला, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.पी. सोजित्रा, श्री भाविन सोजित्रा, जिला विकास अधिकारी श्री परिमल पंड्या, अग्रणी श्री अभयसिंह चौहान, श्री अतुलभाई कानाणी, श्री राजेशभाई भूतैया, श्री चेतन शियाळ, श्री मयूर मांजरिया सहित कई अग्रणी तथा जिले से आए हुए भाई-बहन उपस्थित रहे।

सूरत में अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग, IITian विप्र गोयल के सेमिनार ने आत्मनिर्भर भारत की नई दिशा दिखाई

जीएनएस)। Surat। शहर के प्रतिष्ठित Agarwal Pragati Trust की बोर्ड मीटिंग में 22 मार्च 2026 को एक प्रेरणादायक और दूरदर्शी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें IITian Vipra Goyal ने "जल-ऊर्जा-रोज़गार आत्मनिर्भरता से विकसित भारत उद्देश्य प्राप्ति" विषय पर विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए। यह सेमिनार केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह देश के ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में एक गंभीर पहल के रूप में सामने आया।

सेमिनार के दौरान विप्र गोयल ने अपने प्रेज़ेंटेशन में इस बात पर विशेष जोर दिया कि यदि भारत को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसकी शुरुआत गांवों से करनी होगी। उन्होंने बताया कि जल, ऊर्जा और रोजगार—ये तीन ऐसे स्तंभ हैं, जिन पर आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी जा सकती है। यदि इन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर संसाधनों का सही उपयोग और प्रबंधन किया जाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हुए शहरों पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है।

उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि कैसे जल संरक्षण, सौर ऊर्जा और स्थानीय रोजगार सृजन के मॉडल को गांव-गांव तक पहुंचाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उनका मानना था कि जब गांव मजबूत होंगे, तभी देश सशक्त और विकसित बन सकेगा। उनके विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सामाजिक संवेदनशीलता का समन्वय देखने को मिला, जिसने उपस्थित सभी सदस्यों को प्रभावित किया।

इस अवसर पर ट्रस्ट की कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य—अध्यक्ष Natwarlal Tatanwala, सचिव Brijmohan S Agarwal, पूर्व अध्यक्ष Chiranjilal Agarwal और कोषाध्यक्ष Surendra J Agarwal सहित कई पदाधिकारी और ट्रस्टी उपस्थित रहे। सभी ने विप्र गोयल के प्रेज़ेंटेशन की सराहना करते हुए इसे अत्यंत प्रेरणादायक और समय की आवश्यकता के अनुरूप बताया।

बैठक के दौरान यह सहमति बनी कि केवल विचारों तक सीमित रहने के बजाय इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन-जागरण यात्रा निकाली जाए, जिसके माध्यम से लोगों को जल संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके।

ट्रस्ट के सचिव बृजमोहन एस. अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि विप्र गोयल का यह प्रेज़ेंटेशन एक सकारात्मक और दूरदर्शी पहल है, जो समाज को नई दिशा देने का कार्य कर सकता है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्य इस पहल को आगे बढ़ाने में सक्रिय सहयोग करेंगे।

वहीं अध्यक्ष नटवरलाल टाटनवाला ने इस पहल को समाजहित में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि यदि समाज के जागरूक लोग एकजुट होकर कार्य करें, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना जल्द ही साकार हो सकता है।

कार्यक्रम के अंत में Dr Neelam Goyal ने ट्रस्ट की कोर कमेटी, बोर्ड ट्रस्टी और सभी आमंत्रित सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस राष्ट्रीय पहल में अग्रवाल समाज के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि समाज की भागीदारी से ही इस तरह के अभियानों को सफल बनाया जा सकता है।

इस सेमिनार का प्रभाव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने उपस्थित लोगों के मन में एक नई सोच और ऊर्जा का संचार किया। यह स्पष्ट हुआ कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं और समाज का सहयोग मिले, तो ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना कोई असंभव कार्य नहीं है।

सूरत में आयोजित यह कार्यक्रम इस बात का उदाहरण बनकर सामने आया है कि सामाजिक संगठन किस तरह देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट की यह पहल आने वाले समय में अन्य संगठनों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है।

एक झटके में मिटा हफ्तेभर का फायदा, उतार चढ़ाव के बीच कमजोर बंद हुआ शेयर बाजार

जीएनएस)। नई दिल्ली। बीते कारोबारी सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार ने जहां शुरुआती दिनों में मजबूती का संकेत दिया, वहीं एक दिन की तेज गिरावट ने पूरे सप्ताह की कमाई पर पानी फेर दिया। सप्ताह के अधिकांश सत्रों में खरीदारी का माहौल बना रहा, निवेशकों का भरोसा भी नजर आया, लेकिन गुरुवार को आई भारी बिकवाली ने बाजार की दिशा ही बदल दी और अंततः सप्ताह हल्की गिरावट के साथ समाप्त हुआ। सप्ताह की शुरुआत काफी सकारात्मक रही। शुरुआती तीन कारोबारी सत्रों में BSE Sensex और Nifty 50 दोनों में अच्छी तेजी दर्ज की गई। निवेशकों ने बैंकिंग, आईटी और ऑटो शेयरों में दिलचस्पी दिखाई, जिससे बाजार में उत्साह का माहौल बना रहा। यह तेजी इस उम्मीद पर आधारित थी कि वैश्विक परिस्थितियां स्थिर रहेंगी और घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती बाजार को सहारा देती रहेगी।

हालांकि यह सकारात्मक रुख ज्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रह सका। सप्ताह के चौथे दिन वैश्विक बाजारों से आए नकारात्मक संकेतों ने भारतीय बाजार को भी प्रभावित किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते बाजार में अचानक दबाव बढ़ गया। नतीजतन गुरुवार को जोरदार बिकवाली देखने को मिली, जिसने सेंसेक्स और निफ्टी को भारी गिरावट के साथ बंद होने पर मजबूर कर दिया।

इस एक दिन की गिरावट इतनी तीव्र थी कि उसने सप्ताह के शुरुआती दिनों में हुई बढ़त को लगभग समाप्त कर दिया। निवेशकों के बीच घबराहट का माहौल बन गया और कई लोगों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी। बाजार में यह संदेश साफ था कि मौजूदा समय में स्थिरता की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी हो सकती है।

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आंशिक सुधार जरूर देखने को मिला। कुछ शेयरों में खरीदारी लौटी और सूचकांकों ने थोड़ी बढ़त भी हासिल की, लेकिन यह तेजी सीमित रही। मुनाफावसूली और सतर्कता के चलते निवेशकों ने बड़े दांव लगाने से परहेज किया, जिससे बाजार ज्यादा ऊपर नहीं जा सका।

कुल मिलाकर साप्ताहिक आधार पर देखा जाए तो BSE Sensex और Nifty 50 दोनों ही मामूली कमजोरी के साथ बंद हुए। यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि बाजार में फिलहाल अनिश्चितता बनी हुई है और निवेशक हर छोटे-बड़े संकेत पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सेक्टोरल स्तर पर बाजार का प्रदर्शन मिश्रित रहा। बैंकिंग, एफएमसीजी, फार्मा और ऑयल-गैस सेक्टर में दबाव देखने को मिला, जिससे बड़े शेयरों पर असर पड़ा। दूसरी ओर ऑटो, आईटी और मेटल सेक्टर में कुछ मजबूती देखने को मिली, जिसने बाजार को पूरी तरह गिरने से बचाए रखा। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी मिला-जुला रुख रहा, जहां कुछ कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कई शेयर दबाव में रहे।

विदेशी निवेशकों की गतिविधियों ने भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली करते नजर आए, जिससे बाजार पर दबाव बना रहा। इसके विपरीत घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी कर बाजार को कुछ हद तक सहारा दिया, लेकिन वे विदेशी बिकवाली के असर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सके।

इस दौरान भारतीय रुपये पर भी दबाव बना रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पूंजी के बहिर्वाह का संकेत है। रुपये की कमजोरी का असर आयात आधारित कंपनियों और निवेशकों की धारणा पर भी पड़ा।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बाजार की दिशा काफी हद तक वैश्विक संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों, ब्याज दरों और विदेशी निवेशकों के रुख पर निर्भर करेगी। साथ ही, घरेलू स्तर पर आर्थिक आंकड़े और कॉरपोरेट नतीजे भी बाजार को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस पूरे सप्ताह का सबसे बड़ा सबक यही रहा कि बाजार में तेजी जितनी तेजी से आती है, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो सकती है। एक दिन की बड़ी गिरावट पूरे सप्ताह की मेहनत को मिटा सकती है। ऐसे में निवेशकों के लिए सतर्क रहना, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

वर्तमान परिस्थितियों में बाजार भले ही उतार-चढ़ाव से गुजर रहा हो, लेकिन दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह अवसर भी हो सकता है। हालांकि, अल्पकालिक निवेश करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में अस्थिरता अभी भी बनी हुई है और किसी भी समय अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है।

पाली में दर्दनाक हादसा: तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत, निर्माण स्थल पर सुरक्षा पर उठे सवाल

जीएनएस)। Pali। जिले के सांडेराव थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। निर्माण कार्य के दौरान तीसरी मंजिल से गिरने पर 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि युवक के सिर के बल गिरते ही उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और ऊपर से दीवार का मलबा गिरने से उसकी स्थिति और भी गंभीर हो गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के ढोला गांव में हुआ, जहां एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। मृतक की पहचान Nitesh (25) पुत्र गुलाबराम के रूप में हुई है, जो बालराई गांव का निवासी था और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। बताया जा रहा है कि नितेश रोजाना की तरह काम पर गया था और अन्य मजदूरों के साथ मकान की तीसरी मंजिल पर आरसीसी भराई के कार्य में जुटा हुआ था।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निर्माणाधीन दीवार का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। दीवार के सहारे खड़े नितेश का संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग 35 फीट नीचे जमीन पर सिर के बल जा गिरा। गिरते ही उसकी हालत गंभीर हो गई, लेकिन हादसा यहीं नहीं थमा। तीसरी मंजिल से टूटी दीवार का भारी मलबा भी उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और सिर में गंभीर चोटें आईं।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। साथ में काम कर रहे अन्य मजदूरों ने तुरंत काम रोक दिया और घायल नितेश को संभालने की कोशिश की। बिना समय गंवाए उसे पाली के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों ने उसकी हालत को अत्यंत गंभीर बताते हुए उसे तुरंत जोधपुर रेफर कर दिया।

परिजनों और साथियों को उम्मीद थी कि जोधपुर में उसे बेहतर इलाज मिल सकेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही नितेश ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि नितेश परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसकी असमय मृत्यु से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

घटना की सूचना मिलते ही सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। हालांकि तब तक घायल को अस्पताल ले जाया जा चुका था। पुलिस ने आसपास के लोगों और मजदूरों से पूछताछ कर घटना के बारे में जानकारी जुटाई। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मौके पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिससे हादसे की गंभीरता और बढ़ गई। यदि जांच में लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित ठेकेदार या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

यह हादसा एक बार फिर निर्माण स्थलों पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। अक्सर देखा जाता है कि ऊंचाई पर काम करते समय मजदूरों को न तो सेफ्टी बेल्ट दी जाती है और न ही हेलमेट या अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे में छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो जाती है।

स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना के बाद प्रशासन से मांग की है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि मजदूरों की जान की कीमत पर विकास कार्य नहीं किए जा सकते।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निर्माण स्थलों पर नियमित निरीक्षण, सुरक्षा उपकरणों का अनिवार्य उपयोग और मजदूरों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए, तो इस तरह के हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

पाली में हुआ यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि विकास के साथ-साथ सुरक्षा को नजरअंदाज करना कितना घातक हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और परिजन न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष यह तय करेंगे कि इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल में एलएसडी कांड पर सख्त कार्रवाई, STF के चार पुलिसकर्मी बर्खास्त

जीएनएस)। Shimla। प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच एलएसडी ड्रग्स तस्करी मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के चार पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये सभी आरोपी एसटीएफ की कुल्लू यूनिट में तैनात थे और जांच में इनकी संलिप्तता ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के साथ सामने आने के बाद यह कठोर कदम उठाया गया। इस कार्रवाई ने न केवल पुलिस विभाग में हलचल मचा दी है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नशे के खिलाफ अभियान में किसी भी तरह की ढिलाई या मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा मामला 10 मार्च का बताया जा रहा है, जब न्यू शिमला क्षेत्र में पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर उनके पास से भारी मात्रा में एलएसडी बरामद की थी। इस बरामदगी के बाद शुरू हुई जांच में धीरे-धीरे एक बड़े अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ी तो इस नेटवर्क की कड़ियां विभिन्न राज्यों से जुड़ती नजर आईं और इसी क्रम में केरल के एक आरोपी को Gurugram से गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान सामने आया कि एलएसडी की खेप पहले कुल्लू लाई गई थी, जहां इसे रोकने और जब्त करने की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों की थी, वही इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। आरोप है कि उन्होंने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए तस्करों के साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया। यह खुलासा पुलिस विभाग के लिए बेहद गंभीर और चिंताजनक माना जा रहा है।

प्रारंभिक जांच में संदेह के आधार पर चारों पुलिसकर्मियों को पहले निलंबित किया गया था। इसके बाद विस्तृत जांच और साक्ष्यों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए जब आरोपों की पुष्टि हो गई, तो विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण को अनुशासनहीनता ही नहीं, बल्कि आपराधिक साजिश का गंभीर मामला बताया है। उनका कहना है कि जब कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ने में शामिल पाए जाएं, तो यह पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई आवश्यक होती है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे।

इस घटना के बाद Himachal Pradesh Police ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के खिलाफ उनकी 'जीरो टॉलरेंस' नीति में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। चाहे आरोपी कोई आम व्यक्ति हो या फिर वर्दीधारी, कानून सभी के लिए समान है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस मुख्यालय ने यह भी बताया कि इससे पहले भी ऐसे मामलों में कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। विभाग लगातार अपने तंत्र को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए आंतरिक निगरानी और जांच प्रक्रिया को मजबूत कर रहा है। इस मामले में भी उच्चस्तरीय जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इस नेटवर्क में और लोग तो शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एलएसडी जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता प्रचलन युवाओं के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे न केवल तस्करी के नेटवर्क को तोड़ें, बल्कि समाज में जागरूकता भी फैलाएं।

पुलिस ने आम जनता, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें और यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही इस तरह के अवैध नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 'महिमावंत महेसाणा' के तहत जिले को 938 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भेंट दी

▶▶ विसनगर विकासमय बना
▶▶ राज्य में पिछले तीन दिनों में लगभग 2500 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास सम्पन्न हुआ : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल
▶▶ किसानों के लिए 11,000 करोड़ रुपए के पैकेज और सुदृढ़ स्वास्थ्य-शिक्षा सुविधाओं के साथ गुजरात 'विकसित भारत @2047' के संकल्प की ओर अग्रसर : श्री ऋषिकेशभाई पटेल

जीएनएस)। गांधीनगर : महेसाणा जिले के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को विसनगर में 'महिमावंत महेसाणा' कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 938 करोड़ रुपए की विभिन्न जनहितोन्मुखी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विसनगर तथा महेसाणा जिले के लिए 630 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का शिलान्यास, 168 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का भूमिपूजन तथा 140 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों को जनता के लिए समर्पित किया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजनाएं महेसाणा जिले के सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती माताओं को पोषण किट वितरित की गई। सभी नागरिकों ने मुख्यमंत्री की प्रेरणादायक उपस्थिति में स्वदेशी अपनाने की शपथ ली।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देश में अग्रसर है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महेसाणा जिले के विकास के लिए सरकार के पास भंडार की कोई कमी नहीं है और जिले से आने वाले प्रत्येक उचित कार्य को प्राथमिकता देकर मंजूरी दी जाएगी। राज्य के सर्वांगीण विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन दिनों में ही गुजरात में 2500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। महेसाणा-पालनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण और वर्षों से लंबित तारंगा-अंबाजी रेलवे लाइन को मिली मंजूरी इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति देगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के जन्मस्थान वडनगर को विश्वस्तरीय हेरिटेज टाउन के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने प्रेरणा स्कूल, पुरातात्विक संग्रहालय तथा रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का उल्लेख किया। श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि महेसाणा में उत्तर गुजरात क्षेत्र की रीजनल वाइब्रेंट समिट में हुए 3.24 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जिले के औद्योगिक भविष्य की झलक दिखाते हैं और अब यह जिला फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में भी उभर रहा है। इस अवसर पर ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकास की मशाल को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सरकार की किसानोन्मुखी नीतियों का विवरण देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए 11,000 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण पैकेज घोषित किया है, जिसके अंतर्गत महेसाणा के किसानों को फसल नुकसान के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में जमा की गई है। जिले में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करते हुए विजापुर और खेरालु को सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की भेंट मिली है, साथ ही शिक्षा क्षेत्र में एमएन साइंस कॉलेज के साथ नई कॉलेजों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं।

मंत्री ने आगे कहा कि सुदूरवर्ती व्यक्ति के 'ईज ऑफ लिविंग' में सुधार के लिए सरकार कटिबद्ध है। शहरों को वायर-फ्री बनाने के लिए ऊंझा सहित नगर पालिकाओं में भूमिगत बिजली लाइन बिछाने का कार्य अंतिम चरण में है। मोढेरा के सूर्य मंदिर और वडनगर के ऐतिहासिक गौरव के साथ आधुनिक सुविधाओं का समन्वय करते हुए गुजरात 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में नींव की भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम की शुरुआत में महेसाणा कलेक्टर श्री एस.के. प्रजापति ने अतिथियों का स्वागत किया तथा जिला विकास अधिकारी डॉ. हसरत जैसमी ने आभार व्यक्त किया।

इस गरिमामय कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी, राज्यसभा सांसद श्री मयंक नायक, सांसद श्री हरिभाई पटेल, श्री भरतसिंह डाभी तथा विधायक सर्वश्री मुकेश पटेल, सी.जे. चावड़ा, किरीटभाई पटेल, सुखाजी ठाकोर, सरदारभाई चौधरी एवं राजेंद्रभाई चावड़ा उपस्थित रहे। इसके साथ ही दूधसागर डेयरी के चेयरमैन श्री अशोकभाई चौधरी, अग्रणी श्री गिरीशभाई राजगोर, श्री विनोदभाई पटेल तथा यूजीवीसीएल के एमडी श्री एम.एफ. चौधरी सहित बड़ी संख्या में नागरिक और अधिकारी उपस्थित रहे।

सूरत में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 का प्रेरक आयोजन, 60 विद्यार्थियों को मिली नई उड़ान

जीएनएस)। सूरत। समाज में शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए Rotary International के अंतर्गत रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 द्वारा सूरत में एक भव्य और प्रेरणादायक स्कॉलरशिप अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि यह उन सैकड़ों सपनों की कहानी था, जो आर्थिक अभाव के कारण अधूरे रह जाते हैं और जिन्हें इस पहल ने नई उड़ान देने का कार्य किया।

इस कार्यक्रम में सूरत क्षेत्र की 13 रोटरी क्लबों ने एकजुट होकर 60 ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की, जो प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। ये विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपने करियर का निर्माण कर रहे हैं। इस पहल का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मेधावी छात्र केवल आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने सपनों से समझौता न करे।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों के चेहरों पर झलकती खुशी और आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण थे कि यह सहायता उनके लिए केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और आत्मबल का स्रोत है। कई छात्रों ने इस मंच पर अपने संघर्षों की कहानी साझा की—किसी के पिता मजदूरी करते हैं, तो किसी की मां घरेलू कामकाज से परिवार चलाती हैं। ऐसे हालात में उच्च शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए एक सपना था, जो अब रोटरी की इस पहल से साकार होता नजर आ रहा है।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित Amardeep Singh Bynite ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि आज जिन विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिल रही है, वे आने वाले समय में देश के भविष्य को दिशा देने वाले जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे इस अवसर को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक जिम्मेदारी के रूप में देखें।

विशिष्ट अतिथि Jigneshbhai Desai ने अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज में असमानता को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। उन्होंने रोटरी क्लबों के इस प्रयास को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस अवसर पर Nilesh Shah और Vipul Patel ने भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि रोटरी केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छात्रों के समग्र विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम का सफल संचालन Vikrambhai Sanghani के कुशल नेतृत्व में किया गया। उनकी योजना और समर्पण के कारण यह आयोजन न केवल व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ, बल्कि यह छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक यादगार अनुभव भी बन गया।

इस आयोजन में रोटरी का मूल मंत्र "Service Above Self" पूरी तरह जीवंत दिखाई दिया। निस्वार्थ सेवा की भावना के साथ विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का यह प्रयास समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा। यह केवल आर्थिक सहायता का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह उन मूल्यों का प्रतीक था, जो समाज को जोड़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं।

इस स्कॉलरशिप कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि इसमें केवल वर्तमान जरूरतों को नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखा गया। छात्रों को यह संदेश दिया गया कि वे अपनी सफलता के बाद समाज को लौटाने की भावना रखें, ताकि यह सहयोग की श्रृंखला आगे भी जारी रह सके।

सूरत जैसे औद्योगिक शहर में, जहां अवसर तो बहुत हैं लेकिन संसाधनों की असमानता भी मौजूद है, ऐसे कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। यह पहल न केवल छात्रों को आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाती है कि समाज उनके साथ खड़ा है।

कार्यक्रम के अंत में यह भावना स्पष्ट रूप से सामने आई कि जब समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर शिक्षा के लिए कार्य करते हैं, तो वह केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 का यह प्रयास आने वाले समय में और अधिक लोगों को प्रेरित करेगा और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मजबूत आधार बनेगा।

इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा में किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। 60 विद्यार्थियों को मिली यह छात्रवृत्ति केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह 60 परिवारों के सपनों, संघर्षों और उम्मीदों का प्रतीक है, जो अब एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

कोटा में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या से दहशत, लूट के बाद वारदात की आशंका

जीएनएस)। Kota। शहर के आरके पुरम थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आने से पूरे इलाके में भय और बेचैनी का माहौल बन गया है। खड़े गणेश जी मंदिर के पास गणेश नगर स्थित मकान नंबर 632 में रहने वाली बृजेश कुमारी शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है।

घटना का खुलासा रविवार सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब दूध सप्लाई करने वाला व्यक्ति रोज की तरह घर पहुंचा। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर उसे संदेह हुआ, जिसके बाद आसपास के लोगों को बुलाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। जब घर के भीतर प्रवेश किया गया तो बृजेश कुमारी शर्मा का शव पड़ा मिला। इस दृश्य को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस घर के हर कोने की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। प्रारंभिक जांच में घर का सामान अस्त-व्यस्त पाया गया, जिससे लूटपाट की आशंका और मजबूत हो गई है।

मृतका के बेटे Rakesh Sharma ने बताया कि घर से सोने-चांदी के जेवर, नकदी और कुछ जरूरी दस्तावेज गायब हैं। उन्होंने आशंका जताई कि बदमाशों ने पहले लूटपाट की और फिर हत्या को अंजाम दिया। यह भी सामने आया है कि महिला घर में अकेली रहती थीं, जबकि उनका बेटा पास ही रंगबाड़ी विनोबा भावे नगर क्षेत्र में रहता है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना से एक दिन पहले गणगौर पूजा के अवसर पर महिला ने काफी मात्रा में सोने के गहने पहने थे। ऐसे में यह संभावना भी जताई जा रही है कि किसी ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और मौका पाकर वारदात को अंजाम दिया। इस पहलू को भी पुलिस गंभीरता से जांच में शामिल कर रही है।

मामले में एक और अहम पहलू सामने आया है। पड़ोसियों ने बताया कि एक ऑटो चालक अक्सर महिला के घर आता-जाता था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और उस व्यक्ति की पहचान तथा उसकी गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा पारिवारिक विवाद की बात भी सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मां-बेटे के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था, हालांकि पुलिस इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की पुष्टि कर रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच हर संभव एंगल से की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। एफएसएल टीम द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारण और समय को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। लोग अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोग अक्सर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि वे आसान लक्ष्य माने जाते हैं। ऐसे मामलों में पड़ोसियों की सतर्कता, स्थानीय पुलिस की गश्त और तकनीकी निगरानी बेहद जरूरी होती है।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारत में पुलिस हिंसा की स्वतंत्र जांच और सुधारों की मांग की है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारतीय सरकार से कानून प्रवर्तन के तहत यातना से संबंधित सैकड़ों मौतों और हजारों चोटों के आरोपों की तत्काल स्वतंत्र जांच शुरू करने और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़े सुधार करने का आह्वान किया है।

"ये आरोप कानून प्रवर्तन हिंसा की एक व्यवस्थित तस्वीर पेश करते हैं, जो जीवन के अधिकार, यातना पर पूर्ण प्रतिबंध और गैर-भेदभाव के अधिकार का उल्लंघन करती है। हमें गहरा दुख है कि पुलिस ने इस ऑपरेशन में उचित प्रक्रिया और न्यायसंगत आचरण के बजाय मनमानी हिंसा का सहारा लिया। प्रत्येक घटना की जांच लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तुरंत, स्वतंत्र रूप से और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। विशेषज्ञों को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि पुलिस अत्यधिक और घातक बल का प्रयोग कर रही है, अक्सर बड़े पैमाने पर। उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में पुलिस ने "मुठभेड़" और "अर्ध-मुठभेड़" की हैं। हिरासत में व्यापक यातना की भी खबरें हैं। इस यातना ने मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और हाशिए पर पड़े समुदायों को असमान रूप से प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि "मुठभेड़ और अर्ध-मुठभेड़" एक व्यापक और अमानवीय प्रथा को छिपाती हैं जो गैरकानूनी हिंसा को सामान्य बनाती है और कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास को कमजोर करती है। यह एक जोखिम भरा कार्य है। कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही में महत्वपूर्ण कमियां इस स्तर के दुर्व्यवहार को संभव बनाती हैं। इसलिए, न्याय की मांग करने वालों को चुप कराना न्यायसंगत नहीं है। लोकतांत्रिक समाज। विशेष प्रतिवेदकों ने इस मुद्दे पर भारत सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अधिकारियों को तकनीकी सलाह प्रदान करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है।

IDBI बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी, ओएफएस के जरिए नए निवेशकों को जोड़ने की रणनीति

जीएनएस)। नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI Bank में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार बिक्री पेशकश यानी ओएफएस (Offer for Sale) के माध्यम से बाजार में अतिरिक्त शेयर जारी कर बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना सकती है। यह कदम न केवल बैंक के शेयर मूल्यांकन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, बल्कि इससे निवेशकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास भी मजबूत होने की उम्मीद है। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत के आसपास ही सीमित है, जो किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के लिए अपेक्षाकृत कम मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम सार्वजनिक हिस्सेदारी होने के कारण शेयर के वास्तविक मूल्य का निर्धारण प्रभावित होता है और बाजार में इसकी लिक्विडिटी भी सीमित रहती है। यही कारण है कि सरकार अब इस हिस्सेदारी को बढ़ाने के विकल्प तलाश रही है। बैंक की स्वामित्व संरचना में Life Insurance Corporation of India की प्रमुख भूमिका है, जिसके पास लगभग 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है और बैंक का नियंत्रण भी इसी के पास है। वहीं केंद्र सरकार की हिस्सेदारी करीब 45.48 प्रतिशत है। इस तरह बैंक में कुल मिलाकर सरकारी नियंत्रण बेहद मजबूत है, जबकि आम निवेशकों की भागीदारी बहुत कम है।

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सार्वजनिक हिस्सेदारी को बढ़ाकर 10 से 15 प्रतिशत तक लाया जाता है, तो इससे शेयर बाजार में बैंक के स्टॉक की बेहतर खोज (price discovery) संभव हो सकेगी। साथ ही, निवेशकों की भागीदारी बढ़ने से बाजार में पारदर्शिता भी आएगी और बैंक की साख मजबूत होगी। इस दिशा में ओएफएस को एक प्रभावी और व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए बिना नियंत्रण खोए सरकार और एलआईसी अपनी कुछ हिस्सेदारी बाजार में उतार सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस ओएफएस प्रक्रिया को एक या दो चरणों में लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि बाजार पर अचानक दबाव न पड़े और निवेशकों को भी पर्याप्त अवसर मिल सके। इस तरह की रणनीति से धीरे-धीरे सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है और बैंक के शेयर को स्थिरता भी मिल सकती है।

गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार और एलआईसी ने मिलकर IDBI बैंक में अपनी बहुमत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन यह प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी। संभावित खरीदारों की ओर से प्राप्त वित्तीय बोलियां सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम थीं, जिसके चलते इस योजना को रद्द करना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद अब सरकार वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रही है, जिसमें ओएफएस प्रमुख विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ओएफएस के माध्यम से हिस्सेदारी बढ़ाने से बैंक को निजीकरण की दिशा में एक संतुलित कदम माना जा सकता है, जहां नियंत्रण बरकरार रखते हुए बाजार की भागीदारी बढ़ाई जाती है। इससे बैंक की कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार और निवेशकों के लिए बेहतर अवसर पैदा हो सकते हैं।

इसके अलावा, सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ने से बैंक के शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जिससे निवेशकों के लिए खरीद-बिक्री आसान हो जाएगी। यह कदम दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बैंक की बाजार स्थिति को मजबूत करने में सहायक साबित हो सकता है।

वित्तीय बाजार के जानकारों का कहना है कि यदि यह योजना सफल होती है, तो यह अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। इससे सरकार को अपनी परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, IDBI बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाने की यह पहल केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि सरकार इस योजना को किस तरह लागू करती है और इसका बैंक तथा बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती: 1228 नर्सिंग अफसरों को नियुक्ति, पारदर्शी भर्ती से युवाओं को मिला भरोसा

जीएनएस)। Lucknow। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1228 चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राजधानी स्थित लोकभवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने 492 अभ्यर्थियों को स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे, जबकि शेष 736 अभ्यर्थियों को प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और दो प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

यह आयोजन केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह प्रदेश सरकार की उस नीति और प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बना, जिसके तहत युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को Uttar Pradesh Public Service Commission द्वारा संपन्न कराया गया, जिससे चयन प्रक्रिया में मेरिट और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

कार्यक्रम में उपस्थित उपमुख्यमंत्री Brajesh Pathak, राज्यमंत्री तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी ने इस अवसर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नर्सिंग का पेशा आज केवल देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मांग में है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित और समर्पित नर्सिंग स्टाफ स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होता है और इनकी भूमिका मरीजों के उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बीते वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले जहां स्वास्थ्य क्षेत्र संसाधनों की कमी और अव्यवस्था से जूझ रहा था, वहीं अब सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इसे मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रणाली के कारण अब युवाओं में विश्वास बढ़ा है और उन्हें यह भरोसा हुआ है कि उनकी मेहनत का उचित मूल्यांकन होगा।

सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में नौ लाख से अधिक सरकारी भर्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने इसे राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को भी व्यापक रूप से विकसित किया है।

प्रदेश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या अब 80 से अधिक हो चुकी है और "एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज" की अवधारणा को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। बंद हो चुके एएनएम और जीएनएम प्रशिक्षण संस्थानों को पुनः संचालित किया गया है और उनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके।

इन नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में की जाएगी। इनमें आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा और बदायूं जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जेके कैंसर संस्थान और हृदय रोग संस्थान, कानपुर में भी इनकी नियुक्ति की जाएगी।

विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि चयनित अभ्यर्थियों में 1097 महिलाएं और 131 पुरुष शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि नर्सिंग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और वे स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान कई चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह अवसर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना की और विश्वास जताया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बड़ी संख्या में नियुक्तियां स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अस्पतालों में पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ होने से मरीजों को बेहतर देखभाल मिलती है और स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यक्षमता भी बढ़ती है।

यह पहल न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार सृजन और सामाजिक विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है।

लोकभवन में आयोजित यह कार्यक्रम एक सकारात्मक संदेश लेकर आया, जिसमें युवाओं के सपनों को साकार करने के साथ-साथ प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आने वाले समय में इन नर्सिंग अधिकारियों की सेवाएं प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।